'दिल्ली' से मांगा इंदिरा आवास का रुपया

राज्य ब्यूरो, पटना : ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने 'दिल्ली' (केंद्र सरकार) से इंदिरा आवास की दूसरी किस्त तुरंत मांगी है। उन्होंने इस बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश को पत्र लिखा है। नीतीश ने जयराम के उस दावे को खारिज किया है कि बिहार के पास ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है। नीतीश ने पत्र में लिखा है–'केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण योजना (इंदिरा आवास) का कार्यान्वयन बाधित है।'

पत्र के अनुसार श्रम बजट के अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराए। राज्य सरकार ने पंचायतों में निधि प्रवाह बनाए रखने के लिए अपनी ओर से 520 करोड़ की राशि उपलब्ध करा रखी है।

पर्याप्त राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 8 लाख रुपये प्रति पंचायत की औसत से 8406 पंचायतों के लिए कम से कम 670 करोड़ रुपये के रिजर्व फंड की आवश्यकता है। राज्य सरकार स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है, और इसके लिए श्रम एवं सामग्री का 60:40 का अनुपात पंचायत स्तर पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।